ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2020; 6(12): 410-414
www.allresearchjournal.com
Received: 05-10-2020
Accepted: 07-11-2020

Ravi Prakash
JBT Teacher, Govt. Primary School Bhotwas Bhondu, Rewari, Haryana, India

Corresponding Author:
Ravi Prakash
JBT Teacher, Govt. Primary School Bhotwas Bhondu, Rewari, Haryana, India

पगड़ी संभाल जट्टा कृषक आंदोलन की पृष्ठभूमि

Ravi Prakash

सारांश
प्रस्तुत अध्ययन ब्रिटिशकालीन भारत में ब्रितानी हुकूमत द्वारा कृषि पर थोपे गए तीन काले कानूनों के फलस्वरूप उत्पन्न असंतोष की व्याख्या करता है जिसके अंतर्गत तत्कालीन ब्रितानी हुकूमतों के विरुद्ध जन्मा पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन एक सफल कृषक आंदोलन के रूप में उभरा जिसने आम जनमानस को भी पूरी तरह प्रभावित किया । कृषक आंदोलन होने के अतिरिक्त इस आंदोलन ने स्वतंत्रता के नायकों को एक मजबूत राजनीतिक मंच प्रदान करने का भी कार्य किया जिसकी सफलता अंग्रेजो के प्रति भारतीय नागरिकों में उत्पन्न विद्रोह की भावना मुख्य थी । अतः इस विषय पर अध्ययन करना शिक्षाविदों तथा इतिहासकारों की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में प्रचलित सोच को और भी विकसित करेगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर एकत्रित हुआ किसान वर्ग एक विस्तृत आंदोलन के रूप में उभरा है अतः यह विषय इस अध्ययन की प्रासंगिकता पर बल देता है।

कूट शब्द: कृषक आंदोलन, तीन काले कानून, भारत

प्रस्तावना
भारत के किसान वास्तव में उत्पीड़न तथा शोषण के लंबे समय से शिकार रहे हैं और इस दुर्भाग्यपूर्ण परिणिती में कुछ परिस्थितियों का और कुछ शासन की दुर्भाग्यपूर्ण नीतियों का हाथ रहा है। औपनिवेशिक भारत में किसान आंदोलनों के पैदा होने का प्रमुख कारण तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय कृषि में किए गए परिवर्तन मुख्य रूप से उत्तरदाई माने जाते रहे हैं। भारत में कृषक आंदोलनों का इतिहास अत्यधिक गौरवशाली व प्राचीनतम माना गया है जिसने समय-समय पर सत्ताधारी हुकूमत द्वारा मनमाने ढंग से थोपे गए कानूनों अथवा प्रावधानों का पुरजोर खंडन किया है और अंततः सफलता के नए आयामों को स्थापित किया है । पगड़ी संभाल जट्टा कृषक आंदोलन भी इसी श्रंखला कि एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता रहा है । वर्ष 1907 का कृषक आंदोलन पगड़ी संभाल जट्टा कृषक आंदोलन के रूप में तत्कालीन पंजाब (हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी पाकिस्तान) राज्य से एक व्यापक जन आक्रोश के रूप में उत्पन्न हुआ जिसका नेतृत्व शहीद भगत सिंह के चाचा जी सरदार अजीत सिंह संधू कर रहे थे ।

इस ऐतिहासिक कृषक आंदोलन को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि 1857 की क्रांति के 50 वर्ष पूरे हो रहे थे ऐसी परिस्थिति में तत्कालीन सरकार के विरुद्ध उत्पन्न हुआ यह आक्रोश 9 महीने बीत जाने के पश्चात भी शान्त होने का नाम नहीं ले रहा था और अतंत अंग्रेजी सरकार द्वारा क्रांतिकारियों के समक्ष घुटने टेक देना इस आन्दोलन को सबसे बड़ी व ऐतिहासिक उपलब्धियों का एक हिस्सा बनी।

अध्य्यन उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य पगड़ी संभाल जट्टा कृषक आंदोलन की पृष्ठभूमि का अध्ययन करना है जिसके अंतर्गत तत्कालिक कृषक असंतोष के प्रमुख कारणों का विश्लेषण किया गया है। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश कानूनों के स्वरूप का अध्ययन करना भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है ।

ब्रिटिश कानूनों का स्वरूप

पंजाब भूमि उपनिवेशीकरण अधिनियम

इस विधेयक के अनुसार खाली पड़ी भूमि पर नहर परियोजनाओं के माध्यम से बसाई गई कॉलोनियों में कृषि अनुदान के रूप में वितरित करना था।

1879 में अंग्रेजों द्वारा लायलपुर और पंजाब की अधिकतर खाली पड़ी जमीन अथवा चारागाह योग्य वनीय भूमि पर उद्योग धंधे व बसावट करने की दृष्टि से एक योजना बनाई गई जिसका प्रमुख उद्देश्य चिनाब नदी के पानी को लायलपुर तक पहुंचाना था। इसका एक अन्य पहलू यह भी था कि ब्रिटिश हुकूमत अपने प्रति वफादार भारतीय मूल के अंग्रेजी सैनिको और फौजियों अथवा लोगों को पुरस्कार स्वरूप वहां बसाना चाहती थी। इस दृष्टि से अधिकतर खाली पड़ी भूमि पर नहर बनाकर कॉलोनियों का निर्माण करने की परियोजना अमल में लाई गई जिसके अंतर्गत चिनाब कॉलोनी तथा चुनियन कॉलोनी का निर्माण का लक्ष्य रखा गया। इन कॉलोनियों के निर्माण हेतु बहुत बड़ी तादाद में श्रमिकों की आवश्यकता थी जिसकी आपूर्ति अंग्रेजी शासन द्वारा पंजाब के लोगों को औने पौने दामों में कई सुविधाओ के साथ जमीन देने का वायदा किया गया अथवा उन्हीं श्रमिकों को वहां रहने हेतु आवास उपलब्ध कराए जाने संबंधी वायदे किए गए। लायलपुर, लाहौर अमृतसर जालंधर और आसपास के जिलों के किसान अपने आवासों को त्याग कर नए स्थान पर जाकर बसना शुरू कर चुके थे जिनके कठिन परिश्रम ने बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित कर दिया । लगभग 80% भूमि 50 एकड़ तक की छोटी जमीनों के रूप में अनुदानित की गई। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने अपनी बनाई परियोजनाओं के कानूनों में परिवर्तन कर स्वयं को उस उपजाऊ भूमि का स्वामी घोषित कर दिया तथा किसानों के लाभांश में कमी कर दी गई। किसानों पर कई तरह के पानी संबंधी कर तथा भूमि कर थोप दिए गए। ऐसी परिस्थितियां किसान वर्ग के लिए असंतोष का प्रमुख कारण बनी जिन्होंने आगे चलकर एक वृहद कृषक आंदोलन का रूप लिया। ऐसा माना जाता है कि ऐसा कानून बनाकर सरकार चाहती थी कि थोड़े से विदेशियों को तमाम जमीन का मालिक बना दिया जाए और हिंदुस्तानी काश्तकार यह जमीदार उनके दबाव में रहे। इसके अतिरिक्त सरकार यह भी चाहती थी कि पंजाब में भी अन्य प्रांतों की भांति बड़े बड़े जमींदार हो और शेष गरीब काश्तकार हो। इस प्रकार जनता दो वर्गों में विभक्त हो जाए। मालदार लोग कभी भी किसी भी हालत में सरकार विरोधियों का साथ देने का साहस नहीं कर सकेंगे। [5]

इसके अतिरिक्त इस बिल में यह भी प्रावधान किया गया था कि इन बस्तियों के किसानों को हर चौक पर कम से कम 55 पेड़ लगाने होंगे । परंतु उन्हें अनुमति के बिना पेड़ काटने पर सजा का प्रावधान भी किया गया था।

पंजाब नहर बस्ती विधेयक

तत्कालीन पंजाब सरकार ल्यालपुर आसपास के वीरान क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि में बदलने की दृष्टि से चिनाब नदी के जल को ल्यालपुर तक पहुंचाने की योजना बना रही थी जिसके अंतर्गत बारी दोआब क्षेत्र में आसपास के क्षेत्रों के लोगो को लाया जाने लगा। जिसके परिणाम स्वरूप कॉलोनियों का निर्माण किया गया। इसी दौरान सरकार ने बारी डोआब नहर से लिए जाने वाले पानी के दाम बढ़ा दिए। जिसके चलते ल्यालपुर और रावलपिंडी सर्वाधिक प्रभावित हुए।

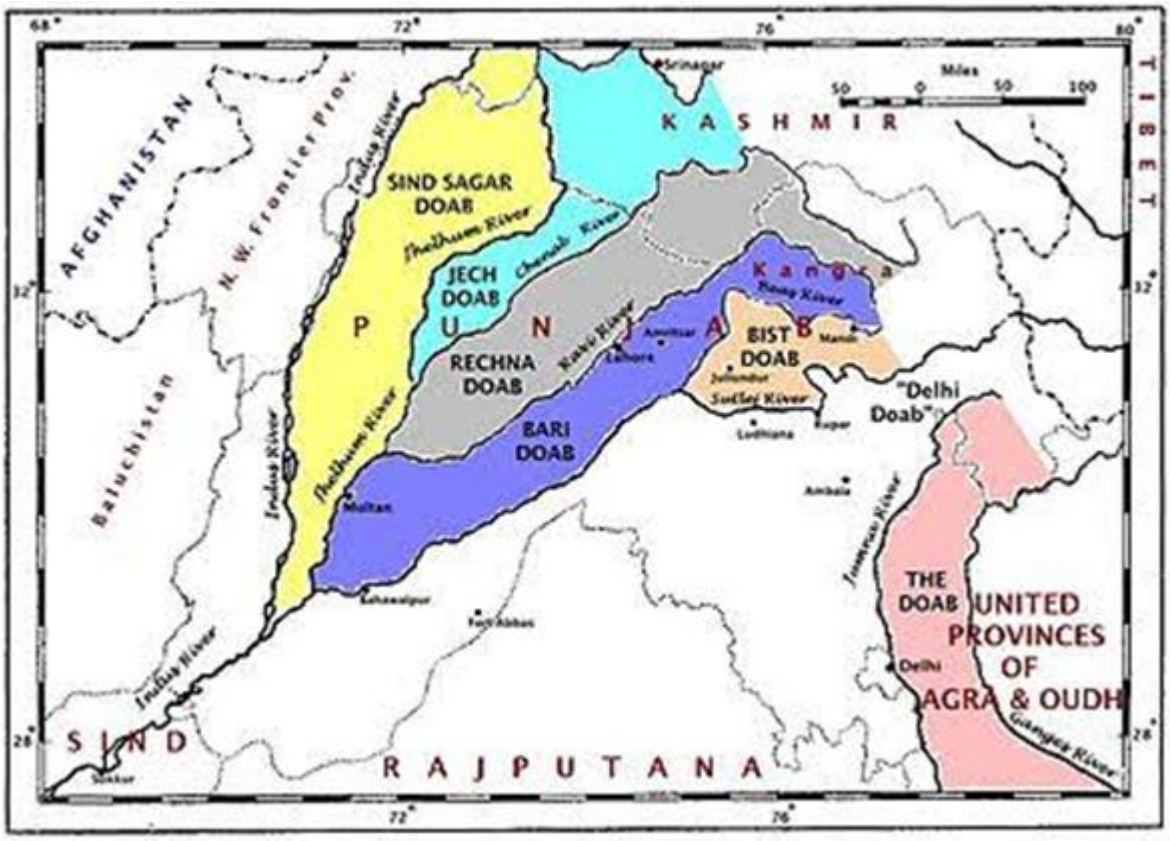

चित्र 1: पांचों दोआबो का भौगोलिक मानचित्र

गौरतलब है कि रावी तथा व्यास नदियों के मध्य के दोआब को बारी दोआब के रूप में जाना जाता है जिसकी चित्र 1 में बैंगनी रंग से प्रदर्शित किया गया है । इस प्रकार जल करो में इस वृद्धि ने पंजाब के लोगो मे ब्रितानी सरकार के प्रति द्वेष उत्पन्न करने का काम किया जिसके परिणाम बड़ी बड़ी कृषक रैलियों के रूप में देखने को मिले ।

पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम

इस एक्ट के तहत कृषि भूमि के मालिक की मृत्यु हो जाने की दृष्टि में उस भूमि पर किसान के बड़े बेटे को ही कृषि करने का अधिकार दिया गया। परंतु बड़े बेटे की अयोग्यता अथवा मृत्यु की दशा में यह अधिकार छोटे बेटे या परिवार के अन्य सदस्यों को ना देकर जमीन के समस्त अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथों में चले जाते थे अथवा उस भूमि को सरकारी भूमि घोषित कर दिया जाता था। किसान उस जमीन पर कोई भी कार्य नहीं कर सकता था पेड़ काटने से लेकर पशु चराने तक की मनाही थी तथा कानूनों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान किया गया था।

पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि -

पगड़ी संभाल जट्टा कृषक आंदोलन की व्यापकता का एक अन्य पहलू बंगाल विभाजन (बंग भंग विभाजन) को भी समझा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी जिसके कारण भारतीय जनता में असंतोष पूर्व में ही विद्यमान था इसी दौरान पंजाब में नए कृषि तथा जल करों में वृद्धि वालें कानूनों ने आग में घी डालने का काम किया। जिसका प्रमुख केंद्र तत्कालीन लायलपुर(आज का फैसलाबाद) तथा रावलपिंडी रहे। इन्हीं क्षेत्रों में किसानों द्वारा दिन प्रतिदिन बड़ी रैलियों को संबोधित किया जाने लगा तथा कृषि कानूनों से होने नुकसान को समझाने के प्रयास भी तेज हुए। सरदार अजीत सिंह संधू इस कृषक आंदोलन के एक प्रखर नेता के रूप में उभरे जिन्होंने कृषि करो के विरोध के साथ साथ भारतीय जनता में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति विद्रोह की भावना को दृढ़ करने का काम किया। इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित शहीद भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह द्वारा क्रांतिकारी विचारों से भरपूर एक संस्था लाहौर में बनाई गई जिसे भारत माता सोसायटी' या महबूब- ए- वतन के नाम से जाना गया । इस संगठन के संस्थापकों में किशन सिंह, महाशय घसीटाराम, स्वर्ण सिंह और सूफी अंबा प्रसाद थे। अजीत सिंह और भारत माता सोसायटी के सदस्य कृषक सभाओं को बलवा करने पर प्रेरित करते रहे। अजीत सिंह किसान रैलियों में ढाई फीट के डंडे पर लगा एक तिरंगा झंडा हाथ में लिए श्रोताओं को कहने लगे की झंडे के डंडे से अंग्रेजों को मार भगाएंगे ।[3]

सरदार अजीत सिंह संधू के प्रयासों का ही नतीजा था कि उनकी रैलियों में एक बड़ा जनसैलाब उमड़ने लगा था जनता

उन्हें बड़े चाव से सुनती थी। इसी क्रम में 21 अप्रैल 1907 में लायलपुर के जमींदारों ने एक कृषक सभा का आयोजन किया जिसमें लाला लाजपत राय मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए। लाला लाजपत राय का लायलपुर रेलवे स्टेशन पर एक भारी भीड़ ने स्वागत किया अन्य वक्ताओं ने कृषि सभा को संबोधित किया वही' झांग स्याल' पंजाबी समाचार पत्रिका के संपादक बांके दयाल द्वारा पगड़ी संभाल जट्टा ओ पगड़ी संभाल ओए गीत गाकर इस आंदोलन को एक नई पहचान व ऊर्जा देने का कार्य किया। लाला लाजपत राय ने पंजाबी में कई लेख लिखे।

लेफ्टिनंट गवर्नर सर चार्ल्स रिवाज के विदाई आगमन पर अमृतसर के खालसा कॉलेज के छात्रों बड़ा प्रतिकूल प्रदर्शन किया। वकीलों और आर्य समाज के सदस्यों ने बड़ी सभाएं आयोजित की।[7]

चूंकि वर्ष 1907 था 1857 की क्रांति को 50 वर्ष पूरे हो रहे थे इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को इसी बात की चिंता थी कि कहीं यह क्रांति दोबारा ना दोहराई जाए। इन्हीं उद्देश्यों से अंग्रेजी सरकार आंदोलन से जुड़े प्रमुख सेनानियो को चिन्हित कर गिरफ्तार करने लगी ।

पगड़ी संभाल जट्टा इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसने आम जनमानस पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी जिसकी सफलता यह थी कि लोग घरों से बाहर निकलते समय भी पगड़ी संभाल जट्टा गीत गाते हुए कृषि आंदोलन में भाग ले रहे थे। [1]

सरदार अजीत सिंह संधू की वाणी में तेजस्विता ने उनके पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन बनाने का भी कार्य किया इसकी पुष्टि लाला लाजपत राय के भाषण से की जा सकती है जिसमें वे कहते हैं कि," सरदार अजीत सिंह का असली उद्देश्य इस किसान आंदोलन को पूरी तरह भड़का कर इसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ उग्र क्रांतिकारी आंदोलन बना देना था। सरदार जी कोई समझौता नहीं चाहते थे बल्कि वे तो अंग्रेजी राज्य का मुकम्मल खात्मा चाहते थे।" [2]

सरदार अजीत सिंह का प्रभाव इस आंदोलन को लेकर इतना बढ़ चुका था कि ब्रिटिश सेना में कार्यरत भारतीय फौजियों पर भी इसका प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता था ब्रिटिश सेना में शामिल सैनिक सरदार अजीत सिंह से मिलकर उन्हें पूर्ण समर्थन का भरोसा देने लगे थे। इस बात के स्पष्ट संकेत रावलपिंडी में 2 अप्रैल को आयोजित एक किसान सभा में दिखाई दिए।

किसान सभा में सम्मिलित भारी जन सैलाब को देखकर ब्रिटिश कमांडर ने भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया परंतु सैनिकों ने अपनी संगीने कमांडर की ओर घुमा ली । अतः यह निश्चित हो चुका था कि पगड़ी संभाल जट्टा कृषक आंदोलन को अब सैनिकों का साथ भी मिल रहा था। ब्रिटिश हुकूमत के प्रति लोगों में जनाक्रोश अपने चरम पर था ।

पंजाबियों के इसी आक्रोश का जिक्र करते हुए लॉर्ड मिंटो ने डनलप स्मिथ को लिखा कि, "वर्तमान स्थिति में औरतों का पंजाब की राजनीति में बढ़-चढ़कर भाग लेना सबसे हैरान कर देने वाली घटना है। जिस प्रकार औरतें, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए पैसा इकट्ठा कर रही थी, यह नए आंदोलन की आने वाली लहर की ओर संकेत करता था।"

लोगों ने अंग्रेजों को परेशान करना शुरू कर दिया, उन्हें मारा-पीटा गया, सरकारी इमारतों और चर्चों को तोड़ा गया, टेलीफोन लाइनों को काट दिया गया तथा कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया।

अजीत सिंह ने लायलपुर को कृषक विद्रोह का केंद्र बनाने के कारणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि' इस क्षेत्र का नया-नया ही विकास हुआ है यूं तो पंजाब के हर हिस्से के लोग यहां रहते हैं परंतु पूर्व सैनिकों की जनसंख्या अधिक है। क्योंकि उनका मानना था कि पूर्व सैनिक अपने साथ अन्य सैनिकों को भी ला सकेंगे जिससे इस आंदोलन को और भी बल मिलेगा।' [4]

शांतिपूर्ण रूप में प्रारंभ हुआ यह कृषक आंदोलन अब उग्र होता जा रहा था जिसके कारण तत्कालीन ब्रिटिश सरकार तीनों काले कानूनों में संशोधन हेतु तैयार हो गई।

दी कोजेज ऑफ प्रेजेंट दिस्कोंटेंट इन इंडिया' पुस्तक में ओ' डानेल लिखते है कि, "सन् 1891 में पंजाब से मिलने वाले भू राजस्व की संख्या 15 लाख पोंड थी, 1906 तक यह 30% बढ़कर 10,9,25000 पौंड है गई।" [6] जिसके स्पष्ट कहा जा सकता था कि कृषि कानून थोप कर पंजाब सरकार ने कृषकों के लाभांश में बहुत बड़ी कमी की थी जिसका सर्वाधिक लाभ भू राजस्व के रूप में सरकार द्वारा अर्जित किया गया। उक्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि तीनों कृषि कानून लाकर ब्रिटिश सरकार का प्रमुख उद्देश्य राजस्व के रूप में धन एकत्रित करना था ना कि किसानों को लाभ पहुंचाना।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के विश्लेषण के पश्चात यह कहा जा सकता है कि पंजाब का कृषक आंदोलन ब्रिटिश शासन काल में एक व्यापक कृषक आंदोलन के रूप में प्रारंभ होकर सैनिकों तथा आम नागरिकों तक पहुंचा जिसने अंग्रेजों के प्रति असंतोष को बढ़ाने का काम किया जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता आंदोलन की गति को और भी बल मिला। सरदार अजीत सिंह, सरदार किशन सिंह, लाला लाजपत राय और सूफी अंबा प्रसाद के अथक प्रयासों का ही परिणाम था कि तत्कालीन पंजाब सरकार को कृषि कानूनों पर पीछे

हटना पड़ा। इसके पश्चात किसान नेताओं की गिरफ्तारियां हुई जिसके अंतर्गत लाला लाजपत राय तथा सरदार अजीत सिंह को गिरफ्तार कर बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया अजीत सिंह के भाई सरदार किशन सिंह को ब्रिटिश सैनिकों ने नेपाल से गिरफ्तार किया। लाला लाजपतराय की रिहाई कराने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा निरंतर प्रयास किए जाते रहे और अंततः 18 नवंबर 1907 लाला लाजपत राय को रिहा कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में यह कृषक विद्रोह स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के पश्चात भी उतना ही प्रासंगिक नजर आता है जितना कि औपनिवेशिक भारत में। इस आंदोलन की सजीवता को 113 वर्ष के पश्चात भी भारत में हो रहे कृषि कानूनों के विरोध में स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है ।

संदर्भ सूची

1. डॉ मीणा अग्रवाल, लाला लाजपतराय, डायमंड बुक्स प्रकाशन, पृष्ठ 45
2. वीरेंद्र सिंधु (2009), युगद्रष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे, राजपाल एंड संस पब्लिशिंग, पृष्ठ 79
3. डॉ श्याम सिंह तंवर, श्रीमती मृदुलता, भूल बिसरे क्रांतिकारी, पृष्ठ 47
4. वहीं पृष्ठ 49
5. राज शेखर व्यास (2008) मृत्युंजय भगत सिंह, ग्रंथ अकादमी प्रकाशन पृष्ठ 149
6. ओ डनेल, दी कोजेज ऑफ प्रेजेंट दिस्कोंटेंट इन इंडिया, पृष्ठ 94
7. खुशवंत सिंह, सिखों का इतिहास भाग 1, किताब घर प्रकाशन दिल्ली, पृष्ठ 158